ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

उदयपुर, गुरूवार 29 जनवरी 2026

वर्ष 2 अंक 264

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती है डिप्टी CM



24 न्यूज अपडेट

मुंबई। वरिष्ठ नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर एनसीपी और भाजपा नेतृत्व के बीच चर्चा तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने पर विचार चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर उन्हें आगे के राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा की है। सुनेत्रा पवार को अब बारामती संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी इस प्रस्ताव पर आगे की बातचीत करेंगे। वहीं, पार्टी के अंदर शरद पवार गुट से विलय को लेकर भी संवारने की कोशिशें जारी हैं।

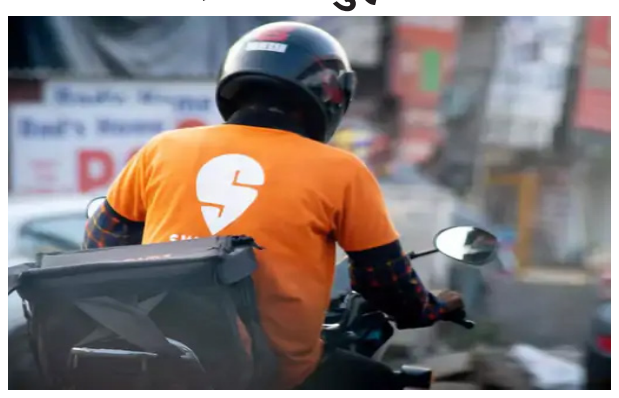
बारामती में अंतिम विदाईः देशभर से उमड़ा जनसैलाब

अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में बड़े सम्मान के साथ किया गया। पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, जबकि सुनेत्रा पवार ने गंगाजल छिड़ककर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शरद पवार, सुप्रिया सुले और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों समर्थक अंतिम दर्शन के लिए बारामती पहुंचे। देर रात से लोग पहुंचने लगे और सुबह होते ही कई मार्गों पर भीड़ से जाम की स्थिति बनी। समर्थक बाइक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बस से आए तथा अंतिम यात्रा में कई किलोमीटर तक लगातार भीड़ दिखी। महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।

बारामती एयरपोर्ट हादसाः कैसे हुआ विमान क्रैश?

बुधवार सुबह लगभग 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर अजित पवार का चार्टर्ड विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि पहले लैंडिंग के प्रयास में रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, जिससे पायलट ने विमान को फिर से ऊँचाई पर उठाया। दूसरी कोशिश में विमान रनवे पर पहुंचने से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस भीषण हादसे में अजित पवार के साथ उनके सुरक्षा कर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू सदस्य की भी मौत हो गई। पवार 66 वर्ष के थे और आगामी जिला परिषद चुनावों के लिए कई रैलियां संबोधित करने वाले थे। विमान ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स का कहना है कि विमान में कोई तकनीकी दोष नहीं था और पायलट के पास 16,000 घंटे जबकि को-पायलट के पास लगभग 1,500 घंटे का अनुभव था।

40% गिग वर्कर्स की कमाई 15 हजार से कमःइकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश; वेटिंग पीरियड के पैसे देने का सुझाव



24 न्यूज अपडेट

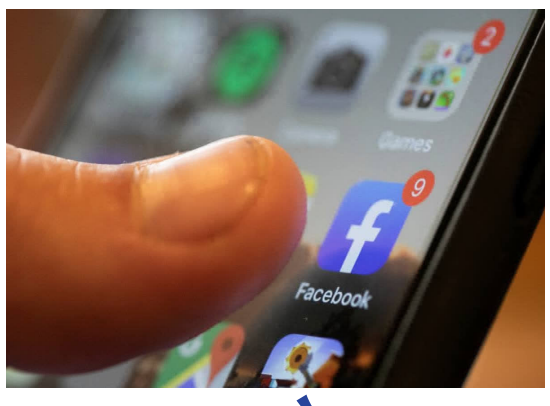
संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमी पर चिंता जताई गई है। सर्वे के मुताबिक, भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15 हजार रुपए से भी कम है।

रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा या प्रति टास्क के आधार पर 'मिनिमम अर्निंग' तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है।

आय में उतार-चढ़ाव सबसे बड़ी चुनौती, लोन मिलने में दिक्कत

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि गिग वर्कर्स की फिक्स्ड इनकम न होने के कारण इन्हें बैंक से लोन मिलने या अन्य फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठाने में मुश्किल आती है। सरकार का मानना है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से गिग वर्क चुनें, न कि मजबूरी में।

Economic Survey 2025-26: बढ़ती डिजिटल लत पर सरकार ने जताई चिंता, सख्त कदमों की जरूरत



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्लीः 'डिजिटल एडिक्शन' में बढ़ोतरी को देखते हुए, वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में इस समस्या से निपटने के लिए बड़े उपायों की जरूरत बताई गई है, जो किशोरों के साथ-साथ वयस्कों की शिक्षा, कार्यस्थल पर उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. 'डिजिटल एडिक्शन' से आशय डिजिटल उपकरणों (स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग) के बिना कंट्रोल उपयोग से है.

संसद में बृहस्पतिवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा में डिजिटल उपकरणों की लत को किशोरों और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाली एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में बताया गया और ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई. इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के अलावा कई तरीकों की जरूरत बताई गई.

डिजिटल लत बनी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता

इसमें कहा गया है कि किशोरों में डिजिटल उपकरणों की लत दुनिया भर में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई है, जिससे सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों और नागरिक समाज से नियम बनाने, इलाज और शिक्षा से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

इसमें जिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, जापान जैसे देशों और अमेरिका के कुछ राज्यों ने डिजिटल उपकरणों की लत की समस्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. समीक्षा में कहा गया है, ''भारत में डिजिटल लत से निपटने में एक बड़ी चुनौती इसकी व्यापकता और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस आंकड़ों की कमी है.''

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) के नेतृत्व में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आगामी दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) से भारतीय संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर व्यवहारिक और काम आने वाली जानकारी मिलने की उम्मीद है.

इसमें कहा गया है कि डिजिटल एडिक्शन पर शोध से युवाओं में अलग-अलग खतरे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नतीजे सामने आए हैं. समीक्षा में कहा गया है कि ''सोशल मीडिया की लत का बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी और सोशल मीडिया पर बुलिंग से पैदा हुए तनाव से गहरा संबंध है तथा कई भारतीय और वैश्विक अध्ययनों में 15-24 साल के लोगों में इसके ज्यादा पाए जाने की पुष्टि हुई है.''

सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82,566 पर बंदःनिफ्टी भी 73 अंक चढ़ा, ऑटो और IT शेयर्स में बिकवाली



24 न्यूज अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी 29 जनवरी को तेजी रही। सेंसेक्स 221 अंक की तेजी के साथ 82,566 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी करीब 73 अंक की तेजी रही, ये 25,416 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में ऑटो, फार्मा और IT शेयर्स में गिरावट रही।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा-नए नियम बनाओ



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाकर केंद्र सरकार और आयोग—दोनों को बड़ा संदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक नियमों के प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट और संतुलित नहीं किए जाते, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या की पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नए नियमों की भाषा और दायरा कई सवाल खड़े करता है। अदालत ने माना कि नियमों का उद्देश्य भले ही उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव की रोकथाम बताया गया हो, लेकिन इसकी व्याख्या और क्रियान्वयन में असंतुलन की आशंका नजर आती है।

यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए नए यूजीसी नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और नियमों के ड्राफ्ट पर दोबारा विचार कर उसे संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कॉलेज परिसरों की जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि अगर किसी छात्र के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी होती है, लेकिन आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं है, तो क्या नए नियम ऐसे मामलों का समाधान कर पाएंगे? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इन प्रावधानों के तहत रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दों का प्रभावी समाधान संभव है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि इससे एक वर्ग को पहले से ही आरोपी और दूसरे को पीड़ित मान लिया जाता है। इससे विश्वविद्यालयों में भय और अविश्वास का माहौल बनने की आशंका है। वहीं कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि समाज और समुदाय स्थिर नहीं होते—समय के साथ उनमें आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर के विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों में पहले से ही तीखी बहस चल रही है। एक ओर इसे ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को सुरक्षा देने वाला कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इससे संस्थानों की स्वायत्तता, मेरिट और निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

बजट में जनजाति बहुल क्षेत्रों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले जिलाध्यक्ष पुष्कर



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान सरकार के आगामी बजट में जनजाति बाहुल्य विधानसभाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा,शिक्षा,पेयजल ,सड़क आदि से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यों को लेकर भाजपा उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भेट कर क्षेत्र की मांगो को लेकर सुझाव पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा । जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने विगत दो बजट में उदयपुर को काफी कुछ दिया है । इस बजट में जनजाति बाहुल्य विधानसभाओं ओर क्षेत्रों हेतु स्वास्थ्य,सड़क,शिक्षा, पेयजल,कौशल विकास,ग्रामीण रोजगार आदि विविध कार्यों हेतु सुझाव एवं मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया है । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आश्वस्त किया है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास में सरकार हर अच्छे सुझाव ओर कार्यक्रमों को बजट घोषणा पत्र में सम्मिलित करेगी और पर्याप्त बजट आवंटित किया जायेगा । इस अवसर पर खेरवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक नाना लाल अहारी एवं धरियावद विधानसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा भी उपस्थित रहे ।

सोना एक दिन में 10,705 बढ़कर 1.75 लाख पहुंचाःचांदी 4 दिन में 62,283 महंगी, 3.80 लाख हुई, दोनों ऑल टाइम हाई पर



24 न्यूज अपडेट

चांदी-सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,76,121 रुपए पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी कमी आई और ये 10,705 रुपए बढ़कर 1,75,340 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले सोना कल 1,64,635 रुपए पर था। वहीं चार कारोबारी दिनों में सोना 21,030 महंगा हो चुका है। 23 जनवरी को ये 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 21,721 रुपए बढ़कर 3,79,988 रुपए किलो पर पहुंच गई है। चार दिन में चांदी की कीमत 62,283 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रुपए किलो थी।

संपादकीय : हादसे के सबक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दीं, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है । पुणे जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है, मगर सवाल है कि इससे पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं से क्या सरकारी तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया? आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। अगर स्थिति वास्तव में जोखिमपूर्ण थी, तो विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई ? दूसरा, यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में क्या ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है ? गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिला के बारामती में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे आने के बाद उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। इससे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे दिग्गजों की भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब 'नहीं' था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक चक्कर लगाया। इससे स्पष्ट है कि हवाई अड्डे पर परिस्थितियां विमान को उतारने के अनुकूल नहीं थी। यह दावा भी किया जा रहा है कि दूसरी बार पूछे जाने पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर सवाल है कि क्या किसी तरह के जोखिम की आशंका के बीच विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है? अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकल कर उन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी के नाम और चिह्न के साथ-साथ दल के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद वे राजगनीत महायुति में शामिल हो गए थे। उनके नेतृत्व वाली राकांपा ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनाव में शरद पवार की अगुआई वाली पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसके बाद सियासी गलियारों में अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलें भी जोर पकड़ रही थीं। ऐसे में विपक्षी दल इस हादसे की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विमान दुर्घटना की निष्पक्ष और गहन जांच हो, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें । सरकारी तंत्र को भी इस तरह के हादसों से सबक लेकर व्यवस्था में जरूरी सुधार करने चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई विमान दुर्घटना न हो।

नियमों का विरोध

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के आधुनिक परिवेश में भी समाज में जातिगत भेदभाव की धारणा बनी हुई है। यहां तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जाति के आधार पर भेदभाव के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं । इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम जारी किए हैं। मगर इनको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो कुछ अधिकारी भी इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही नहीं, अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। सवाल है कि आखिर यूजीसी के इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल, कुछ लोगों को आशंका है कि आयोग के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि न तो किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा और न ही नियमों के बेजा इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि यूजीसी ने नियमों का जो नया प्रारूप जारी किया है, उसे लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है और नियमों का पालन न करने पर संस्थान पर कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली के एक नगर मजिस्ट्रेट और अयोध्या में एक जीएसटी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, यह नए नियमों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसमें दोराय नहीं कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, उनका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मसले पर संयम और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

11 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन झुका, 5 लाख मुआवजे व 7 दिन में सड़क निर्माण पर बनी सहमति



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर. स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहे 11 वर्षीय मासूम की मिनी ट्रक से कुचलकर मौत के बाद गुरुवार को उदयपुर का नाकोड़ा नगर–रकमपुरा मार्ग आक्रोश का केंद्र बन गया। क्षेत्रवासियों के तीन घंटे चले उग्र प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने तथा सात दिन में सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। घटना बुधवार शाम प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के सामने नाकोड़ा नगर रोड पर हुई। अशापुरा नगर निवासी गोरांग शर्मा (11) स्कूल से छुट्टी के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर पहले से मौजूद गड्ढे में साइकिल फिसलने से वह गिर पड़ा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे मिनी ट्रक का टायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसा इतना भयावह था कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मिनी ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू की। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। गुरुवार को नाकोड़ा नगर, रकमपुरा सहित आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने उदयपुर–डबोक एयरपोर्ट नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि बार-बार शिकायतों के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिसका खामियाजा एक मासूम को जान देकर चुकाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शी अमित तातेड़ ने बताया कि गोरांग का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। सड़क पर बने गड्ढे के कारण वह गिरा और पीछे से आई गाड़ी ने उसे कुचल दिया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। उन्होंने कहा कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा। इसके बाद 7 से 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिला प्रशासन से वार्ता के लिए रवाना हुआ। वार्ता के बाद क्षेत्रवासी जीवन सोलंकी ने बताया कि प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने तथा क्षेत्र में सात दिन के भीतर सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही हादसे वाले स्थान पर मौजूद गड्ढे को भर दिया गया है। सहमति बनने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

खाओ-खिलाओ संस्कृति जिंदाबाद : कानून के रखवाले नहीं, वसूलीबाज कहिये, डूंगरपुर में एसीबी ट्रैप से खाकी पर फिर लगा दाग



24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। डूंगरपुर में पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता उस वक्त कठघरे में आ गई, जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोवड़ा थाने के एक हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को रिश्वत के जाल में दबोच लिया। मामला किसी मामूली लेन-देन का नहीं, बल्कि एक ऐसे कथित समझौते का है, जिसमें एफआईआर दर्ज न करने के बदले मोटी रकम तय की गई थी।

एसीबी की कार्रवाई में हेड

कॉन्स्टेबल अशोक कुमार पाटीदार और कॉन्स्टेबल प्रकाश पाटीदार को 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। हालांकि, दोनों पुलिसकर्मी रकम लेकर मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में आसपुर रोड पर एक होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि फिलहाल बरामद नहीं हो सकी है।

खाकी वर्दी में रिश्वतखोर मामले की शुरुआत 18 जनवरी को हुई, जब एक युवक ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, नयागांव क्षेत्र में खड़े होने के दौरान दोवड़ा थाने की पुलिस गाड़ी वहां आकर रुकी। बहाने से नाम-पता पूछा गया, मोबाइल फोन लिया गया और उसी मोबाइल के आधार पर उसे ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी में लिप्त बताया गया। शिकायत में बताया गया कि पुलिसकर्मी ने मोबाइल में लेन-देन का हवाला देते हुए उसे गाड़ी में बैठाया और थाने ले जाने की बात कही। रास्ते में खुद को कॉन्स्टेबल प्रकाश पाटीदार बताकर कहा गया कि अगर मामला दर्ज हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी।

2 लाख नहीं दोगे तो केस कर देंगे

परिवादी का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दो लाख रुपये की मांग रखी और कहा कि रकम देने पर न एफआईआर दर्ज होगी, न मोबाइल जब्त किया जाएगा। कई दिनों तक बातचीत चलती रही। बाद में रकम घटाकर डेढ़ लाख रुपये पर सौदा तय हुआ। एसीबी ने शिकायत की सत्यता जांची, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद बुधवार रात ट्रैप की कार्रवाई की गई। तय योजना के तहत परिवादी को रकम के साथ भेजा गया। पैसे कार के डैशबोर्ड पर रखवाए गए और उसे रास्ते में उतार दिया गया।

फिल्मी अंदाज में फरारी, फिर गिरफ्तारी

जैसे ही एसीबी को इशारा मिला, टीम हरकत में आई। लेकिन तब तक आरोपी पुलिसकर्मी कार लेकर फरार हो चुके थे। देर रात तक तलाश के बाद उन्हें पुनाली के आगे एक होटल के पास दबोच लिया गया। तलाशी में रिश्वत की रकम नहीं मिली, जिससे जांच की दिशा अब बरामदगी और पूछताछ पर टिक गई है।

सिस्टम पर गहराता सवाल इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या थानों में कानून अब भी न्याय का औजार है या डर दिखाकर सौदेबाजी का जरिया बनता जा रहा है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और रिश्वत की राशि जल्द बरामद की जाएगी।

बांद्रा टर्मिनस–उदयपुर सिटी रेलसेवा सहित कई ट्रेनें रेगुलेट



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। पश्चिम रेलवे के सफाले–केलवे रोड रेलखण्ड पर ब्रिज संख्या 114 पर तकनीकी कार्य के चलते ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण संबंधित रेलखण्ड पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा और उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ रेलसेवाएं निर्धारित समय से विलंबित रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री शशि किरण के अनुसार उक्त तकनीकी कार्य के कारण निम्न रेलसेवाएं पश्चिम रेलवे क्षेत्र में रेगुलेट रहेंगी—

रेगुलेट की जाने वाली रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से): गाड़ी संख्या 22901 बांद्रा टर्मिनस–उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, 31.01.26 को बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करने पर 1 घंटा 20 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 12978 अजमेर–एर्नाकुलम एक्सप्रेस, 30.01.26 को अजमेर से प्रस्थान करने पर 15 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 09626 दौंड–अजमेर स्पेशल, 30.01.26 को दौंड से प्रस्थान करने पर 1 घंटा रेगुलेट। गाड़ी संख्या 12940 जयपुर–पुणे एक्सप्रेस, 31.01.26 को जयपुर से प्रस्थान करने पर 50 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 30.01.26 को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करने पर 30 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 12956 जयपुर–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, 31.01.26 को जयपुर से प्रस्थान करने पर 20 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, 31.01.26 को भगत की कोठी से प्रस्थान करने पर 30 मिनट रेगुलेट। गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़–दादर एक्सप्रेस, 31.01.26 को हनुमानगढ़ से प्रस्थान करने पर 30 मिनट रेगुलेट।

एनिकट निर्माण के दौरान हादसा, मलबे में दबने से दो मजदूरों की जान गई



24 न्यूज अपडेट

सलूंबर। सलूंबर जिले की ईसरवास पंचायत के मानपुरा क्षेत्र में चल रहे एनिकट निर्माण कार्य के दौरान बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। जोधसागर तालाब के समीप निर्माण स्थल पर अचानक पत्थरों का भारी हिस्सा ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब साढ़े पांच बजे निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक ऊपर से पत्थर खिसक कर नीचे आ गिरे। चीख-पुकार मचते ही आसपास मौजूद ग्रामीण और अन्य मजदूर मौके पर दौड़े। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया गया और दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। घायलों को तत्काल सलूंबर जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहां इलाज के दौरान झल्लारा थाना क्षेत्र के जेतेला फला निवासी प्रभुलाल मीणा (45) और कचरा मीणा (32) ने दम तोड़ दिया। हादसे में थावरा मीणा (45), गौतम मीणा (50) और प्रभु मीणा (45) गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सभी मजदूर लांबी डूंगरी के पास स्थित जेतेला फला गांव के रहने वाले बताए गए हैं।

सलूंबर थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि दोनों मृतक मजदूरों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर हादसे के कारणों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अवधेश मीना, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला, डिप्टी एसपी हेरम्भ जोशी और तहसीलदार डॉ. मयूर शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस हादसे के बाद एनिकट निर्माण कार्य को लेकर विभागीय जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जल संसाधन विभाग और जल ग्रहण योजना विभाग—दोनों के अधिकारियों ने इस निर्माण कार्य से अपने-अपने विभाग का कोई संबंध होने से इनकार किया है। ऐसे में यह निर्माण किस एजेंसी के अधीन हो रहा था, यह जांच का अहम बिंदु बन गया है। हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। अब प्रशासन के सामने न केवल मृतक मजदूरों के परिजनों को न्याय दिलाने की चुनौती है, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है।

जीप में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर पुलिस कार्यवाही

24 न्यूज अपडेट

खेरवाड़ा, पहाडा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के मध्य नजर थाना अधिकारी उम्मेदी लाल के निर्देशन में क्षेत्र के डेरी गांव में सहायक उप निरीक्षक कालू लाल द्वारा जीप चालक ईश्वर पुत्र हीरा गरासिया निवासी पडलाई थाना विजयनगर जिला साबरकांठा गुजरात के खिलाफ जीप में क्षमता से अधिक सवारी बैठा कर ले जाने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करते हुए चालान काटा गया। जीप में ऊपर नीचे एवं पीछे लटके हुए यात्री पाए गए जो यातायात नियम के विरुद्ध पाया गया। जीप की क्षमता 6 सवारी की थी जबकि उसमें 15 से 20 सवारियों को बिठाकर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर परिवहन किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान चालक द्वारा जीप के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संबंधी कागजात भी उपलब्ध नहीं कराए गए। थाना अधिकारी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर हेड कांस्टेबल अजीत सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

दूसरी कार्यवाही में पाटिया थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव के निर्देशन में हेड कांस्टेबल वालचंद द्वारा कनबई तीन रास्ता पर कमांडर जीप चालक द्वारा जीप को लापरवाही पूर्वक लहराते हुए चलाने एवं सवारी की जान जोखिम में डालने से मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करने का प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण जीप चालक नटवरलाल पुत्र जीवन प्रकाश डोडियार जाती मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी कनबई वाडा घरा के खिलाफ दर्ज किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर हेड कांस्टेबल बदा राम द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

वन्यजीव संकट में अब सीधे 1926 पर कॉल, शहरों में लेपर्ड घुसने पर बनेगा स्पेशल प्रोटोकॉल



24 न्यूज अपडेट

जयपुर. राजस्थान में आबादी क्षेत्रों में टाइगर और लेपर्ड की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सरकार अब आमजन के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू करने जा रही है। इस नंबर पर कॉल कर गांव, कस्बे या शहर में जंगली जानवर के घुसने की तुरंत सूचना दी जा सकेगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सदन में दी। पूर्व मंत्री एवं जयपुर विधायक कालीचरण सराफ द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में वन राज्य मंत्री ने बताया कि फिलहाल जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में आने पर लोग 100 नंबर पर कॉल करते हैं, जिससे समय नष्ट होता है और तब तक मौके पर भीड़ जमा हो जाती है। इसी देरी को खत्म करने के लिए सरकार अब 1926 हेल्पलाइन शुरू कर रही है, जो सीधे वन विभाग से जुड़ी होगी।

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सदन को बताया कि टाइगर या लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में आने पर अब महाराष्ट्र की तर्ज पर विशेष प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। जिस क्षेत्र में जंगली जानवर की मौजूदगी होगी, उसके आसपास करीब पांच किलोमीटर के दायरे में अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। आमजन को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की जन-हानि न हो और वन्यजीव भी आक्रामक न हों। विधायक कालीचरण सराफ ने अपने सवाल में कहा कि जयपुर सहित कई शहरों में लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन आमजन को यह जानकारी नहीं होती कि ऐसी स्थिति में किससे संपर्क किया जाए। लोग पहले 100 नंबर पर फोन करते हैं, वहां से अलग-अलग नंबर बताए जाते हैं और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। पूरक प्रश्न में विधायक ने महाराष्ट्र मॉडल का हवाला देते हुए बताया कि वहां जंगली जानवर के घुसते ही तय दायरे में सख्त प्रोटोकॉल लागू कर लोगों की आवाजाही रोकी जाती है। इस सुझाव की सराहना करते हुए वन राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भी इसी तर्ज पर आगे रेस्क्यू और नियंत्रण की कार्यवाही की जाएगी। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि 1926 हेल्पलाइन प्रक्रियाधीन है और इसे एक माह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में टाइगर और लेपर्ड से जुड़े मामलों में त्वरित सूचना, समन्वय और कार्रवाई संभव हो सकेगी।

बड़ा खुलासा: JE भर्ती 2020 की रद्द परीक्षा का दोबारा हुआ पेपर भी था लीक; SOG ने रैंक 12 वाले सहायक अभियंता को किया गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

जयपुर 29 जनवरी। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 के प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की जांच के दौरान राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। कनिष्ठ अभियंता (JE) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020, जिसे पेपर लीक के कारण रद्द किया गया था, उसके सितंबर 2021 में दोबारा आयोजन में भी पेपर लीक हुआ था। एसओजी ने इस मामले में जालौर के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए वर्तमान में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक सहायक अभियंता गणपत लाल बिश्नोई पुत्र गोवर्धन राम (34) निवासी डेडवा सांचोर को गिरफ्तार किया है, जिसने पेपर लीक के दम पर मेरिट में 12वां स्थान हासिल किया था।

पूछताछ में खुला राज: रद्द परीक्षा के बाद भी नहीं रुका पेपर माफिया

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विशाल बंसल के अनुसार दिसंबर 2020 में हुई JE भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले (सांगानेर थाना FIR 540/2020) की जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछा कि पहली परीक्षा रद्द होने के बाद वे दोबारा सफल कैसे हुए, तो उन्होंने कबूल किया कि 12 सितंबर 2021 को दोबारा आयोजित परीक्षा का पेपर भी परीक्षा से पूर्व ही आउट कर दिया गया था।

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद एसओजी ने 19 जनवरी 2026 को एक नया मामला दर्ज किया है। जांच के केंद्र में कुख्यात पेपर माफिया जगदीश विश्नोई पुत्र हरिराम निवासी डांटा सांचौर है, से पूछताछ में सामने आया है कि जगदीश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर परीक्षा से ठीक पहले अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र मुहैया कराए थे।

मेरिट होल्डर साहब पहुंचे सलाखों के पीछे

जांच में सबसे गंभीर तथ्य गणपतलाल विश्नोई की संलिप्तता का आया है। गणपतलाल ने अवैध तरीके से पेपर हासिल कर परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में 12वां स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में आरोपी बाड़मेर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तैनात था और प्रमोशन भी पा चुका था।

एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी नियुक्ति और पदोन्नति को निरस्त कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

SI भर्ती और JE भर्ती का कनेक्शन

एसओजी की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह वही संगठित गिरोह था जिसने 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक किए थे। यानी महज तीन दिनों के अंतराल में इस गिरोह ने दो बड़ी प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं की शुचिता को पूरी तरह भंग कर दिया था।

"एसओजी इस पूरे नेटवर्क की पहचान कर रही है। हमारा लक्ष्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि अनुचित लाभ लेकर सिस्टम में घुसे ऐसे फर्जी अधिकारियों को बाहर निकालना भी है।

- विशाल बंसल, एडीजी एसओजी, जयपुर

JEE MAIN 2026: पहले सेशन में ही बना रिकॉर्ड, 13 लाख कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा



24 न्यूज अपडेट

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) के पहले सेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B Tech) की परीक्षा बुधवार को समाप्त हो गई है. इस परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के डेटा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जारी किया है. इसके अनुसार इस परीक्षा में जनवरी सेशन में सर्वाधिक कैंडिडेट का रिकॉर्ड बना है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार साल 2026 में जनवरी सेशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 13.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे. इनमें से 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. ऐसे में परीक्षा में यह अपने आप में रिकॉर्ड है. दूसरी तरफ उपस्थित कैंडिडेट्स का प्रतिशत भी बीते 5 साल में सर्वाधिक है और यह अपने आप में रिकॉर्ड बना है. इस बार 96.25 प्रतिशत कैंडिडेट ने परीक्षा दी है. पहले सेशन में यह बीते सालों में सबसे ज्यादा रही है. इससे पहले सर्वाधिक उपस्थित प्रतिशत साल 2025 में था, जहां पर पहले सेशन में 13.11 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें से 12.58 लाख ने परीक्षा दी थी. पहले सेशन में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी साल 2025 में ही थी.

यूनिक कैंडिडेट्स का भी बन सकता है रिकॉर्ड : देव शर्मा ने बताया कि बीते चार साल से दो सेशन में जेईई मेन की परीक्षा आयोजित हो रही है. इस बार भी दो सेशन होंगे. परीक्षा से पहले सेशन से यूनिक कैंडिडेट में बीते 4 सालों में 1.35 से 2.89 लाख कैंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में इस साल 2026 में भी यही माना जा रहा है. करीब 2 लाख विद्यार्थियों के बढ़ोतरी यूनिक कैंडिडेट्स में पहले सेशन से होगी. इसके अनुसार इस बार पहले सेशन में 13 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. परीक्षा देने वाले यूनिक कैंडिडेट की संख्या 15 लाख को क्रॉस कर जाएगी. यह अपने आप में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में एक रिकॉर्ड स्थापित होगा.

12 फरवरी को जारी होगा रिजल्ट : जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन में बीई व बीटेक एंट्रेंस के लिए 5 दिन में 10 शिफ्ट में हुई है. एनटीए की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार 13 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. ऐसे में प्रत्येक शिफ्ट में करीब 1.3 लाख विद्यार्थी बैठे हैं. एनटीए जल्द ही विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रिस्पांस, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी करेगा. एनटीए इन्हें जारी करने के बाद विद्यार्थियों से आपत्ति भी लेगा. इन आपत्तियों का निस्तारण एक्सपर्ट करेंगे, जिनमें कुछ प्रश्नों में विद्यार्थियों को बोनस अंक मिल सकते हैं या फिर कुछ प्रश्नों को परीक्षा से हटाया जा सकता है. ऐसा बीते सालों में हुआ भी है. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, जिसके आधार पर स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा. प्रवेश परीक्षा के जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी 2026 को जारी होगा.

अभी नहीं होगी AIR जारी : देव शर्मा ने बताया कि जनवरी सेशन के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक्स (AIR) जारी नहीं की जाएगी. केवल स्कोर कार्ड परसेंटाइल में जारी किए जाएंगे. इस परसेंटाइल के आधार पर कैंडिडेट यह निर्णय कर सकता है कि उसे दूसरे सेशन अप्रैल की परीक्षा देनी है या नहीं. अप्रैल सेशन के बाद दोनों सत्रों के बेहतर स्कोर के आधार पर जेईई मेन 2026 की ऑल इंडिया रैंक्स (AIR) जारी की जाएगी, इसीलिए अधिकांश कैंडिडेट अपने बेहतर स्कोर के लिए दोनों सेशन की परीक्षा देते हैं. दूसरी तरफ पहले सेशन के बाद रही कमी में सुधार के लिए भी लाखों विद्यार्थी दूसरे सेशन में शामिल होते हैं.

पन्नाधाय महिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों पर उबाल



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर के सरकारी पन्नाधाय महिला चिकित्सालय में प्रसव के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए विप्र महासेना के नेतृत्व में परिजनों व क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार मीना जोशी को 13 जनवरी 2026 को पन्नाधाय महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से ही प्रसूता की हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसकी जानकारी बार-बार डॉक्टरों को दी गई, लेकिन स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। विप्र महासेना के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हेमंत जोशी ने बताया कि हालत में सुधार नहीं होने पर अगले दिन महिला का दोबारा ऑपरेशन किया गया। इसके कुछ समय बाद चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि प्रसूता की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जबकि प्रसव से पूर्व महिला पूरी तरह स्वस्थ थी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में स्थिति गंभीर होने के बाद वे मीना जोशी को इलाज के लिए अहमदाबाद ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ऑपरेशन प्रक्रिया और दी गई दवाओं में गंभीर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गुरुवार को विप्र महासेना के बैनर तले परिजनों और क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

नए यूजीसी नियमों के खिलाफ महासभा राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. अमेरिका सिंह का कड़ा विरोध, तत्काल वापसी की मांग



24 न्यूज अपडेट

लखनऊ। नए यूजीसी नियमों को लेकर देशभर में उठ रहे विरोध के स्वर के बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 मूल ने भी कड़ा रुख अपनाया है। महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने इन नियमों को शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने के लिए घातक बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।

प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार का नारा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास – एक भारत श्रेष्ठ भारत" इन नए यूजीसी नियमों से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सर्व समाज पर जबरन ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं, जो समाज को जोड़ने की बजाय विभाजन की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नियम विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और भविष्य में अपराध व आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे न केवल शिक्षण संस्थानों में वैमनस्यता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा का मूल उद्देश्य भी प्रभावित होगा। प्रोफेसर सिंह ने नए यूजीसी नियमों को "काला कानून" बताते हुए कहा कि यह न तो समाज के विकास में सहायक है और न ही शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला। इसके उलट, यह देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 मूल की ओर से भारत सरकार से स्पष्ट शब्दों में आग्रह किया गया है कि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि विश्वविद्यालयों की गरिमा, स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखा जा सके। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो देशभर में शिक्षाविदों और समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष और गहराएगा।

आदिवासी अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा, तेंदूपत्ता नीलामी की बोली शुरू, 10 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के जंगलों से निकलने वाला तेंदूपत्ता इस बार सिर्फ बीड़ी उद्योग की जरूरत नहीं बल्कि आदिवासी परिवारों की उम्मीदों की फसल बन गया है. चेतक सर्किल स्थित वन भवन में जैसे ही तेंदूपत्ता नीलामी की बोली शुरू हुई, वैसे ही बाजार में हलचल तेज हो गई. शुरुआती दौर में ही 10 करोड़ रुपये से रिवेन्यू का अनुमान लग रहा है. इस बार तेंदूपत्ता की मांग अधिक नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा सरकार के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी समुदायों को मिलेगा.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुनील चिद्री ने बताया कि पिछले बार की तुलना में इस बार 10 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू का अनुमान है. दक्षिणी राजस्थान का तेंदूपत्ता आंध्र प्रदेश सहित देश के अलग-अलग राज्यों में काम में लिया जाता है. इसका निर्यात भी होता है. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों आदिवासी परिवार मार्च से जून तक तेंदूपत्ता संग्रहण करते हैं. अच्छी बोली लगने से उन्हें बेहतर मजदूरी और अधिक काम के दिन मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. बीड़ी उद्योग के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों में भी इसकी मांग बढ़ी है. यही वजह है कि इस नीलामी में देश के अलग-अलग राज्यों जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जयपुर, टोंक सहित कई क्षेत्रों से व्यापारी शामिल हुए हैं.

चिद्री ने बताया कि पूरे संभाग की 74 इकाई की नीलामी प्रक्रिया चल रही है. पिछले साल इसकी नीलामी पर 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था. इस बार अच्छी पैदावार के चलते यह आंकड़ा बढ़ सकता है. मई और जून के महीने में आदिवासी अंचल के लोगों को इससे व्यवसाय मिलता है. वन विभाग की तरफ से तेंदूपत्ता के प्रति बोरे की कीमत 1400 रुपए से अधिक रखी गई है. इस बोली में शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से 124 लोग पहुंचे हैं. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार नीलामी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाई गई है. ज्यादा बोली से सरकार को राजस्व तो मिलेगा ही, साथ ही आदिवासी परिवारों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

पुलिस थाना खेरोदा की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 468.270 किलो डोडा चूरा व स्कॉर्पियो जब्त





24 न्यूज अपडेट

खेरोदा। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना खेरोदा ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 468.270 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री योगेश गोयल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा श्रीमती अंजना सुखवाल एवं वृताधिकारी वृत वल्लभनगर श्री राजेन्द्र सिंह जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी खेरोदा श्री सुरेश विश्नोई मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.01.2026 को नेशनल हाईवे-48 पर वाना चौराहे के पास नाकाबंदी प्रारंभ की गई। नाकाबंदी के दौरान मंगलवाड़ से उदयपुर की ओर आ रही एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर जीजे 35 एच 4403 को रोका गया। पुलिस नाकाबंदी को देखकर चालक ने अचानक गाड़ी को रॉन्ग साइड में मोड़ते हुए मंगलवाड़ की ओर तेज गति से भगा ली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी के इशारे पर वाना चौराहे से मंगलवाड़ की ओर तैनात कांस्टेबल कुलदीप ने स्टॉप स्टिक की सहायता से स्कॉर्पियो का आगे का टायर ब्रस्ट कर दिया। टायर ब्रस्ट होने के बावजूद चालक ने गाड़ी को रॉन्ग साइड में ही दौड़ाना जारी रखा, जिस पर पुलिस टीम ने पीछा कर बमुश्किल वाहन को रुकवाया। गाड़ी रुकते ही चालक व सहचालक सीट पर बैठे दोनों व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर बीच व पीछे की दोनों सीटें खुली हुई पाई गईं, जिनमें काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे। कट्टों को नीचे उतारकर गिनती करने पर कुल 22 कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा होना पाया गया, जिसका कुल वजन 468.270 किलोग्राम निकला। इसके अतिरिक्त वाहन में पांच अलग-अलग नंबरों की नंबर प्लेट भी बरामद की गईं, जिससे तस्करी की साजिश का खुलासा हुआ। इस संबंध में स्कॉर्पियो वाहन के चालक एवं सहचालक द्वारा अवैध डोडा चूरा का परिवहन करना तथा वाहन में अलग-अलग नंबर प्लेट रखना पाए जाने पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने से थाना खेरोदा पर प्रकरण संख्या 18/2026 दर्ज किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान थाना कानोड़ के थानाधिकारी श्री मुकेशचंद पुनि द्वारा किया जा रहा है। मामले में अज्ञात अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस की टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है तथा अनुसंधान जारी है। इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी खेरोदा श्री सुरेश विश्नोई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुनील कुमार 2471, कांस्टेबल बाबूलाल 629, दिनेश 3219, कुलदीप 1536, नितेश कुमार 1207, मनोज कुमार 596 एवं चालक कांस्टेबल नेमीचंद 87 की सराहनीय भूमिका रही।

नराकास उदयपुर की 45वीं अर्द्धवार्षिक बैठक संपन्न, हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर जोर



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), उदयपुर की 45वीं अर्द्धवार्षिक बैठक गुरुवार को भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान आयकर आयुक्त डॉ. रण सिंह (आयकर कार्यालय, उदयपुर) ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना रहा। इस दौरान सदस्य कार्यालयों द्वारा विगत छह माह में हिंदी उपयोग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राजभाषा नियमों की अनुपालना के तहत केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में आगामी छह माह की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना, वार्षिक राजभाषा समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा उदयपुर में अनुवाद प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी टंकण प्रशिक्षण, राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन तथा छह माही रिपोर्ट का समय पर प्रेषण शामिल है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. रण सिंह ने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल औपचारिकता न होकर दैनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सभी कार्यालयों से संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया। नराकास के सचिव श्री पालीवाल ने विगत छमाही में उत्कृष्ट योगदान के लिए आयकर कार्यालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, पंजाब नेशनल बैंक, रेल प्रशिक्षण संस्थान एवं भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुखों की सराहना की। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी।

बैठक के अंत में उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के कार्यवाहक कार्यालय प्रमुख डॉ. चित्तरंजन मंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों को निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया।

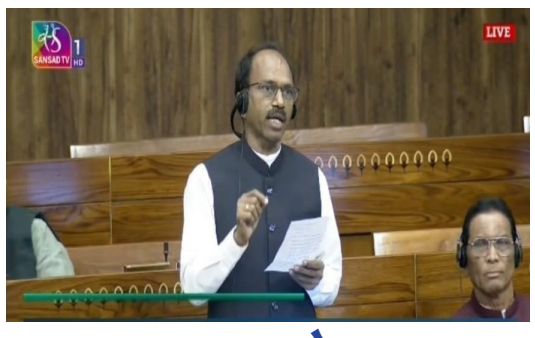
सीटीएई, एमपीयूएटी उदयपुर में किसानों के लिए नीड-बेस्ड नवाचारी कृषि यंत्रों का विकास



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) के कुलगुरु डॉ. प्रताप सिंह ने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग (CTAE) स्थित फार्म मशीनरी एवं पावर विभाग के फार्म मशीनरी परीक्षण केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर विभाग में विकसित नवीन कृषि यंत्रों का निरीक्षण किया गया और वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्र परीक्षण उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। कुलगुरु डॉ. प्रताप सिंह ने किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीड-बेस्ड और नवाचारी कृषि यंत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन यंत्रों का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना है। कृषि कार्यों को सरल, कम लागत वाला और अधिक लाभकारी बनाने के लिए उपकरणों का विकास किसानों की समस्याओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों की विशेष टीमों का गठन किया जाए, जो आसपास के गांवों में जाकर किसानों के साथ संवाद करें और उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। इसके आधार पर कम लागत, सरल और प्रभावी कृषि मशीनों की डिजाइन एवं विकास किया जाएगा। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार तकनीकी समाधान मिलेंगे। कुलगुरु ने यह भी बताया कि आगामी समय में कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ एमओयू किए जाएंगे, ताकि उद्योग-विश्वविद्यालय सहयोग से आवश्यकता-आधारित कृषि मशीनों का संयुक्त विकास किया जा सके। वर्तमान में सीटीएई के वैज्ञानिक बैटरी चालित बीज मसाला एवं स्वीट कॉर्न बुवाई यंत्र, मेहंदी फसल के कटाई यंत्र, बीज मसाला फसलों के थ्रेशर सहित कई नवाचारी कृषि यंत्र विकसित कर रहे हैं। ये यंत्र स्थानीय परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सके। इस अवसर पर मीडिया प्रकोष्ठ एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. जी. एल. मीना ने इस पहल की जानकारी साझा की।

संसद में उदयपुर : सांसद डॉ. रावत का सुझाव माना, ग्राम सभा में बनेगा विकसित ग्राम का प्लान



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत अब प्रत्येक विकसित ग्राम का विकास प्लान ग्राम सभा में तैयार किया जाएगा। लोकसभा में गुरुवार को उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत द्वारा तारांकित प्रश्न के दौरान दिए गए इस सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष एवं जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस सुझाव को व्यवहारिक और प्रभावी बताते हुए इसे लागू करने की बात कही। जनजातीय कार्य मंत्री ने सदन को बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित जनजाति ग्राम अभियान भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 63,843 जनजाति बहुल गांवों को शामिल किया गया है। राजस्थान में यह अभियान 30 जिलों के 208 ब्लॉकों के 6019 ग्रामों में लागू है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ मानव संसाधन विकास को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना है। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस पांच वर्षीय अभियान के तहत 17 मंत्रालयों द्वारा 25 प्रमुख उपायों को लागू किया जा रहा है। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, आजीविका, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान में उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में अभियान के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल आपूर्ति, आवास स्वीकृति और मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सांसद डॉ. रावत ने कहा कि ग्राम सभा में योजना बनने से जनभागीदारी बढ़ेगी और योजनाएं वास्तविक जरूरतों के अनुरूप धरातल पर उतर सकेंगी।

साइकिल पाकर बालिकाओं के खिले चेहरे



24 न्यूज अपडेट

मावली। राज्य सरकार की छात्रा हितैषी योजना के तहत मावली एवं खेमली ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुरुवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने की सुविधा के लिए साइकिलें वितरित की गईं, जिससे छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों, महिलाओं एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें सौंपी गईं। गुरुवार को भीमल, खेमपुर, उदा खेड़ा, ढूंढ़िया, आमली, नूरड़ा, घासा एवं नाहरमंगरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। साइकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इसे अपनी पढ़ाई को नियमित बनाए रखने में सहायक बताया।

शिल्पग्राम में 1 फरवरी को 'गोल्डन बाजार' का मंचन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 जनवरी। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित मासिक नाट्य संध्या 'रंगशाला' के अंतर्गत रविवार 1 फरवरी को 'गोल्डन बाजार' नाटक का मंचन किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक फ़ुरकान खान ने बताया की प्रति माह आयोजित होने वाली मासिक नाट्य संध्या रंगशाला के अंतर्गत पोटली थिएटर ग्रुप मुंबई द्वारा गोल्डन बाजार नाटक का मंचन रविवार 1 फरवरी को सायं 7 बजे शिल्पग्राम उदयपुर स्थित दर्पण सभागार में किया जाएगा। इस मनोरंजक नाटक के लेखक पवन उत्तम एवं विजय सिंह परमार, स्टोरी एवं डिजाईन विजय सिंह परमार तथा संकल्पना अंशु श्रीवास्तव ने की। इस कार्यक्रम में आमजन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

मेवाड़ प्रताप दल की बैठक में बेसहारा लोगों की अस्थियों के विसर्जन का निर्णय



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मेवाड़ प्रताप दल सेवा संस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक नृसिंह द्वारा मीठा राम जी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महंत हर्षितादास जी महाराज उपस्थित रहे। बैठक का संयोजन संस्थान के संस्थापक लाला सालवी ने किया, बकि अध्यक्षता रमेश जी लालवानी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से लावारिस एवं असहाय व्यक्तियों की अस्थियों के विधिवत विसर्जन का निर्णय लिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार आगामी 11 अप्रैल को अशोक नगर स्थित गौशाला श्मशान से सुबह हरिद्वार के लिए यात्रा प्रारंभ की जाएगी। वहां 13 अप्रैल को गंगा तट पर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना के पश्चात अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। संस्थान के जिला सचिव राकेश पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो परिवार अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाना चाहते हैं, वे मेवाड़ प्रताप दल के संस्थापक लाला सालवी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं के पास संस्थान का कोई दायित्व है, उन्हें अपनी-अपनी कॉलोनियों में बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस सेवा कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में इस जनसेवा अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु तय स्थानों पर बैनर लगाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष ओंकार जोशी, महिला अध्यक्ष मंजु गहलोत सहित सुनील अहीर, खुशालेंद्र कुमावत, प्रभुलाल तेली, राजकुमार माली, शैलेन्द्र गावरी, सुरेश नागदा, रानी भाटिया, सुमन, राजकुमारी, हेमलता माली, प्रेमराज माली, घनश्याम भाटी, नरोत्तम गौड़, राकेश खत्री, पंडित गोपाल पालीवाल, सतीश, प्रीतम सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नागरिक सुरक्षा विभाग की मॉक ड्रिल, बालिका विद्यालय, पुलां में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर के पुला क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में गुरुवार दोपहर 3 बजे राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा विभाग मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन कनिष्ठ लेखाकार भावना कंवर के सहयोग से सहायक प्रशासनिक अधिकारी धनेंद्र कश्यप एवं वरिष्ठ सहायक गोविंद जगरवाल के दिशा-निर्देशन में किया गया। अभ्यास के दौरान भवन ढहने (बिल्डिंग कॉलैप्स), आगजनी की स्थिति तथा आपातकालीन बचाव एवं राहत कार्य (इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आपदा के समय घबराहट से बचने, सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने और दूसरों की सहायता करने के व्यावहारिक तरीकों का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में विद्यालय की प्रधानाचार्य सहित समस्त अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं और प्रशिक्षण को गंभीरता से देखा। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी मॉक ड्रिल का उद्देश्य आमजन को आपदा के प्रति जागरूक करना तथा संकट की घड़ी में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।